fAiblic sccior utmost functional autonomy is required. That applies to banks also. These have to function within the framework of transparency. There has to be adequate accountability. Banking being a very sensitive sector, there should be prudential supervision and that is why the Reserve Bank is there to provide prudential supervision of the banking system.

With no prudentials, outside supervision can be a subsitute for self-policing. I have seen only a few days ago a report published by the British Government with regard to what happened to the Bearings, a very ancient merchant bank, which suddenly evaporated. The moral of this is that if internal control systems are not functioning, you may have a very fine outside supervision system. But, in a world that is so complex, where billions and billions of dollars flow across the exchanges overnight, I think no amount of external supervision is a susbtitute, essential though it is for good housekeeping, for strengthening internal control mechansim. So, we have to walk on both legs. We have to strengthen the interna] control system mechanism. At the same time, the Reserve Bank has to be alert to see that we have a proper supervision system and that our banks function subject to prudential regulations. That is the broad approach, Madam, that we have for dealing with the problems of our banking system. Thank you very much, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARADE): Now, the question is:

"That the Bill to amend the Recovery of Debts Due to JJanks and Financial Institutions Act, 1993, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted. THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MANMOHAN SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT MOTION

Draft Agriculture Policy Resolution

THE MINISTER FOR AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): Madam, I beg to move:

"That this House do consider the Draft Agriculture Policy Resolution (as modified) laid on the Table of the House on the 14th May, 1993."

उपसभाध्यक्ष जी, आप लोगों की कृपा हुई तो जो दो साल के बाद आपने समय निकाला। जैसा कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, आपकी कृपा हुई। यह बड़ी कृपा हैं। बहुत दिनों से यह आशा थी। कि आप कुछ आंख खोलेंगे और आपने कृपा आज की हैं। हर एक चीज का शायद समय होता हैं। बहुत दिनों से यह ख्याल था कि हम ऐग्रीकल्चर पालिसी, कृषि निति का निर्धारण करेंगे और उसके लिए पहले काफी समय से, एक नहीं दो नहीं, पहले भानु प्रताप सिंह कमेटी और फिर जोशी कमेटी बनी। फिर एएक चीज आई और फिर वापस चली गई। उसके पश्चात आपने यह जिम्मा मुझे दिया। मैंने सभी साथियों को, सभी एक्सपर्टस को बुलाया फार्म डीलर्स को बुलाया साइंटिस्ट्स को बुलाया। जितने भी साथ मुझे मिल सके उन सब के साथ सलाह-मशविरा करके, विचार करके हमने एक छोटा प्रारूप तैयार किया...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : किसानो को भी बुलाया या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : सब को बुलाया फारमर्स को बुलाया। जो भी किसानों की संस्थाएं थीं उनको बुलाया। जो अपने को ऊंचे फारवर्ड किसा मानते हैं, उनको भी बुलाया। मैंने कहा कि आइए इसमें हमारे ज्ञान में वृद्धि कीजिए यह पालिसी मेरी और आपकी नहीं हैं, किसी एक पार्टी की नहीं हैं, बल्कि यह सब किसानों की

पालिसी हैं और इस हिसाब से जितना भी योगदान आप दे सकते हैं, दीजिए। मैंने कहा कि आइए अआप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत हैं, आपके सजेशंस का स्वागत हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, दिमागी तौर पर कोई चीज बंद कर दी हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी जो स्टेडिंग कमेटी हैं। उसने भी कुछ बातें कही हैं। बात उन्होंने भी वही कही हैं। उन्होंने कहा हैं कि विस्तारपूर्वक करो। बढ़ाओ। मैंने एक ही बात कहनी है कि जो कुछ सारी बातें हैं अगर मैं उनको पढ़ कर बताऊंगा जो ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए जो आपके पास ज्ञान है वह आप हमें देंगे। मुझे तो इतना ही कहना है कि यह एक किस्म के प्रारूप दे दिया था कि यह चीजें हमने देखनी हैं। कहां हमने एगीकल्चर को ले जाना हैं, किस प्रकार से उत्थान करना हैं, किस प्रकार से जमीन की उपजाऊ क्षमता की रक्षा करनी हैं, कैसे पानी का इंतजाम करना हैं, कैसे डाइवर्सीफिकेशन करके किसान की आमदनी को बढ़ाना हैं, किस प्रकार से जैविक रक्षा करनी हैं, किस प्रकार से इनसेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्ज़ से बचाव करना हैं, इंटेग्रटेड मेनेजमेंट करना हैं, किस तरह से फिशिंग कल्चर करना हैं, किस तरह से प्लास्टिक्स को लाना हैं, किस तरह से हॉटीकल्चर का उत्थान करना हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हमने सोच विचार कर के इसका प्रारूप तैयार करके आपके सामने रखा हैं। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान भर मे काफी सारे क्लाईमेट ज़ो हैं जिनमे अलाहिदा अलाहिदा मांग समय के अनुसार होती है और सरज़न के हिसाब से होती हैं। सारा भारतवर्ष एक जैसा नहीं हैं। पूर्व में कुछ हैं पश्चिम में कुछ और हैं, दक्षिण में और उत्तर में कुछ और हैं मैकरो से माईको हम करेंगे। उस वक्त हर रीजन मे अलाहिदा अलाहिदा इम्पलीमेंटेशन के हिसाब से किस प्रकार से हमें बढ़ाना हैं। किस प्रकार से नीति निर्धारित के साथ साथ इसे कार्यरूप में परिणत करना हैं। इस सारे सिलसिले में हमने सोच विचार कर के यह किया हैं। उस वक्त अलहिदा अलहिदा ज़ोन के हिसाब से हम करेंगे। यह प्रारूप रख कर हमने नीति को तैयार किया हैं। इसमें जैसे आपकी इच्छा हो, आप की समझ में जो बात आती हो, कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको दूर करेंगे। मैंने किस प्रकार से किसानों को बरी करवाया हैं सब टेबसेशन से, यहा महामना-महामना बैठे हुए हैं, आपके कुबेर हैं, मैंने इनसे कहा कि किसानों के प्रति ऐसी भावना रखिये क्योंकि सीलिंग के हिसाब से उसकी ज़मीन तो बिल्कुल कम हो गई ळैं। आपने सन् 1950 में सीलिं लगा दी थीं। उसके बाद भगवान ने और सीलिंग लगा दी क्योंकि तीन पीड़ियां आ गई। तीन पीढ़ियों मे एक बाप के दो बेटे,दो के चार चार के छः या आठ बेटे (**व्यवधान**) जितने भी हैं उस हिसाब से भूमि सब से बंटती गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट गई। यह चीज़ आगे चलकर गड़बड़ करेगी क्यिकि किसी वक्त हमें यह सोचना पड़ेगा कि इन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बंट जाने के कारण ज्यादा हम उपज कैसे पैदा करेंगे। एक और देखने की बात है जो मेरे दिमाग में कभी – कभी आती हैं जो आप सब के लिए सोचना जरूरी हैं। मैं आपसे बार-बार प्रार्थना भी करता रहा हूं कि जहां हमारी आबादी 30-32 करोड़ थी आज लगभग 92 करोड़ हो गई हैं। आखिर पृथ्वी कितना भार वहन कर सकती है, यह हमें सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं हमारे मिल कर सोचते हैं। मुझे बड़ी चिन्ता होती हैं क्यो नहीं हम सारी पार्टियां मिल कर एक बात को सोचें कि यह भार हमारे ही सिर पर आएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम क्या कर रहे थे, कुछ तो सोचते। चीन सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? लेकिन अकेली पार्टी कोई नहीं करेगी। हमें इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। डवलप्ड कंट्रीज़ में मैंने देखा हैं जहां तीन –चार-सात खेती में काम करते हैं। हमारे यहां 70 प्रतिशत खेती का काम करते हैं। 70 प्रतिशत से और ज्यादा कितने काम करेंगे? इस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को वहां से निकाल कर कृषि से उद्योग के क्षेत्र में लाना पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र मे लाने के लिए आप को मुल्क में औद्योगिकरण करना पड़ेगा। इसका डाइवर्सीफिकेशन आफ एग्रीकल्चर, रूपांतर जो हमने किया हैं, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए जिस तरीके से हम करना चाहते हैं हम वह चीज़ पैदा करा चाहते हैं जो बाहर के मुल्क पैदा कर रहा हैं। हॉलैंड जैसा मुल्क जो हमारे एक जिले के बराबर हैं, 13 बिलियन के फैलावर पैदा कर सकता हैं तो भारतवर्ष में ऐसे हम पांच सौ हॉलैंड बना सकते हैं। हम क्यो नहीं कर सकते जबकि सारी चीज़ें हमारे पास हैं? आज हमारे गरीब किसान ने नाम पैदा किया हैं। हम फलो के उत्पादन में दुनियां में दुसरे पहले नम्बर पर फलो को उत्पादन सारी दुनियां में करते हैं दूध में सेकेंड नम्बर पर हैं। दो तीन साल में हम ऊपर आने वाले हैं। वेज़ीटेबल्ज़ में दूसरे नम्बर पर हैं, अगे तीन चार साल में पहले नम्बर पर जाने वाले हैं। लेकिन जो हमारे पास नष्ट हो जाता हैं जो दो चार सालों में इसके बाद ऊपर जाने वाला हैं और जो हमारे पास नष्ट भी

होता हैं उसका भी इलाज हैं ...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपके साथी सुन नहीं रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : वे शायद एग्रीकल्वर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) **:** आपका नम्बर तो ऊपर है पर, पर-कैपिटा किना हैं?

श्री बलराम जाखड़ : मैं देखता हूं।

मैं इसी लिए कह रहा हूं कि उसका कैसे होगा। अब 25-26 प्रतिशत जो नष्ट हो जाता है अगर उसको ही रोक लें तो कितना फर्क पड़ता हैं। इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए यही सोचा कि जस्टीफिकेशन के साथ हमने इसके लिए यही सोचा कि जस्टीफिकेशन के साथ हमें क्या करना है। इसमे आपका ग्रेडिंग का बंदोबस्त नहीं था, पैंकेजिंग का हमारे पास बंदोबस्त नहीं था, फारवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन , कोल्ड स्टोरेज को कोई बंदोबस्त नहीं था, न प्रेसोसिंग का बंदोबस्त था, न एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे पास एयरपोर्ट या पोर्ट थे, न गाडियां आदि थीं। कहीं कोई नजारा आज तक किसी ने सोचा नहीं था। वह भी हमने इस पालिसी में सोचा कि इसको किस तरीके से इस स्तर पर लाकर खड़ा करें, जहां हम भी पैसा कमा सकें। मेरे किसान की जेब मे भी पैसा जा सके। वह भी सुख की सांस ले सके। यह जो शहर का गांव की जीवन स्तर का अंतर है इसको मिटा सकें। हम भी कुछ कह सकें कि हम भी आजाद भारत के निवासी हैं हमें भी कुछ हक है जीने का। उसको किस तरीके से बराबर किया जाए इसके लिए एग्रोप्रिएट कंसोर्टियम किस हिसाब से करने चाहिए, किस तरह से कोल्ड स्टोरेज करने हैं, किस तरीके से प्रीकूलिंग स्टेशंस लगाने हैं, किस तरीके से हम सिखाएं-इसी हिसाब से मैंने कोशिश की है हक इतना उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च की तरफ जो दिया। इसके उत्थान के लिए हम 400 करोड़ से 1300 करोड़ तक ले गए हैं। डेरी फार्म में 500 से 1300 करोड़ ले गए हैं। इसी आयकर से साढ़े तीन हजार से साढ़े सात हजार करोड़ एग्रीकल्वर में लिया हैं। येसारी बातें निहित करके हमने यह बनाया है कि हम किस प्रकार से नकशा बदल सकते हैं भारत की कृषि का भारत के किसान की जागृति का और उसको आमदनी देने का। ये सारी बातें इसमें निहित की हैं। लेकिन इसमें अगर आपका कही भी सुझाव हो तो वह आप दे सकते हैं।

इसी तरीके से सब्सिडी की बता जहा तक आती है मैं किसान को देना चाहता हूं। हमारे कुबेर बैंठे हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हैं सोचने का। देखिए अब कई चीजें ऐसी हैं जो इन्वेसटमेंट ओरिएंटेड है। मैं सब्सिडी नहीं कहता हं। सब्सिडी तो वह होती हैं जो मैं मुफ्त में दे दूं। जैसे हम ड्रिप इरीगेशन में, स्प्रिंकलर इरीगेशन में बताते हैं कि कैसे पानी का अच्छा उपयोग करना हैं पानी नहिं हैं। दुनिया भी में पानी की कमी आएगी और यह एक बहुत बड़ा मसला होगा। पानी सोने की कीमत रखता हैं। अभी पिछले दिनो इजरायल के मंत्री आए थे मेरे पास, मिस्टर सुर एग्रीकल्वर के वे बता रहे थे कि 15 साल के बाद इजरायल में हमें रीसाइक्लिड वाटर पीने को मिलेगा। यही यहां होने वाला हैं। लोग पानी का चक्कर करते हैं इसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन गलत हैं। हमें पानी का उपयोग करना है। इस प्रकार से करना है कि उससे सिंचाई भी ज्यादा लेनी है और आमदनी भी ज्यादा लेनी हैं। प्लास्टीकल्वर ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन-इसके लिए 50 प्रतिशत से लककर 75 प्रतिशत जो इसमे लिखा हैं उसको हमने कार्यरूप मे परिणत कर दिया हैं, प्रोक्टिकल शेप दे दी हैं कि किस तरीके से मि नक्शा बदलना चाहते हैं। जहां जहा आम आदमी का ताल्लुक है उसको हम 5 प्रतिशत देंगे जहां हरिजन और गिरिजन हैं और जो हमारी बहनें हैं आपके लिए स्पेशल प्रावधन रखा हैं। हमने उपसभाध्यक्ष महोदया और हमने 75 प्रतिशत आपको दिया हैं जिन-जिन बहिनो के नाम जमीन हैं उनको 75 प्रतिशत देंगे। इसका अंदाजा क्या होगा। अगर मनमोहन जी पैसे देंगे तो डैम बनेगा। ... (**व्यवधान**)

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा) **:** अगर पैसा देंगे तो?

श्री बलराम जाखड़ : देखिए देना मेरे जिम्मे, लेना आपके जिम्मे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) **:** आदिवासियों की जरो जमीन हैं जंगलों में वे फारेस्ट वाले उनको नहीं देते हैं। पहले उसको रेगुलराइज करिए तभी यह जो 50 और 75 प्रतिशत की बात हैं वह होगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं अभी उसकी बात करता हूं वह भी आपके और हमारे जिम्मे काम हैं। आपने और हमने करना हैं।

मैं कहना चाहता था अगर मनमोहन सिह जी डैम बनवाएंगे, अगर गवर्नमेंट डैम बनवाएगी तो सौ रूपए खर्च होंगे, नहर बनवाएगी तो सौ रूपए खर्च होंगे लेकिन यहां मनमोहन सिंह जी 50 रूपए देंगे और 50 रूपए हम देंगे तो हम एक एकड़ की बजाए दो एकड़ में सिंचाई होरी। स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम पैसा देंगे तो हम एक

एकड़ के बजाए ढाई एकड़ में सिंचाई करेंगे और प्रोडक्शन जो ऐ एकड़ में दस मन होता हैं वह होगा उसकी जगह 14-15 मन। तो अंदाजा करिए कि ढाई या तीन, चार पांच गुना पैदा होगा। यह हम करना चाहते हैं। इस हिसाब से हम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इनको मनवाया और यह बात इनहोंने मानी कि हां यह काम तो ठीक है। इसलिए उन्होंने पैसा दिया हैं।

तो इसलिए इन्होंने पैसा दिया। अगली बार और खुला करके देंगे तो औरपैसा दूंगा। लेकिन अभी ते मैं जहां-जहां हा स्टेट में जाता हूं और अभी कल-परसों मैं हैदराबाद उनको कह कर आया हूं, मुझे इस बात को कहते हुए कोई शंका नहीं हैं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार कहीं भी हों, मैं बिल्कुल तैयार हूं, जितना पैसा तुम ले सकते हो हिम्मत है इतनी काम करने की किसान को दो। उसका उतथान होगा। इसी हिसाब से हमकरना चाहते हैं। हमने करवाया हैं। भानु प्रताप सिंह कमेटी ने तो लिखा हैं कि इंडस्ट्री के उसको बराबर नहीं ला सकते। लेनि मेरा ख्याल है कि कुछ बाते हैं कि जहां हम कर सकते हैं। हमने लिखा है कि इंडस्ट्री का दर्जा उसको हम दें और दिया। उसी हिसाब से मैंने उसको खुला किया। पहले तो हमने भारतवर्ष में यह काम किया कि एक स्टेट में, जैसे आप पंजाब में पैदा करो और मद्रास में ले जाओ, तामिलनाडु मे ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं हैं। जहां मर्जी आप अपना सामान लेकर चले जाओ। आपको खुली छूट हैं। सपोर्ट प्राइस के बारे में भी इन्होंने लिखा तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए उसके हिसाब से हमने जितना भी कुछ हो सकता था, वह हमने हमारा जो प्राइस कमीशन है उसको एक-एक चीज़ मे बता कि "ए" से लेकर "जैड" तक हरेक चीज़ को गिनती कर लो, जमीन ले लो, जमीन की कीमत ले लो, उसका ब्याज ले लो, जो उसके साथ इम्प्लीमेट्स हैं, वैल हैं उनका भी लगा लो, बीज कर लो। दवाई कर लो, खाद कर लो, लेबर की लो उसमें जो भी कुछ कर सकते हो वह कर लो जो कि आपको सही-सही पज़र आए।

श्री जगेश देसाई : स्वयं की लेबर भी ।

श्री बलराम जाखड़ : हां, स्वयं की लेबर भी साथ में उसको मैने मैनजमेंट का भी डाल दिया, लेकिन हमने किसी बात को छोड़ा नहीं हैं। इसके अलावा हमने यह भी कर दिया कि जितना ऊंचा बेंच सकते हो बेचो और जहां मर्जी बेचो। आप अंदाजा कर लीजिए।

तकरीबन-तकरीबन गेहूं और ध्यान के बगैर अब कोई चीज़ में जरूरत नहीं हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की, थोड़ा सा सीरियल्स हैं, बाकी तिलहन में नहीं, कॉटन में नहीं, ये चीज़ों में किसी में करने की जरूरत नहीं हैं। हम तो वह देते हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। फिलहाल आपको भी बता देना चाहता हूं शायद आपको ज्ञान हो, आपको पता होना चाहि कि इस साल जिस तरीके से फसल पैदा हुई और रेकार्ड उत्पादन हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार जो रेकार्ड उत्पादन था उससे भी ऊपर ले गए 19 करोड़ टन अनाज आपने इस साल पैदा किया। और सरकार नहीं खरीदती कई लोग तो कहते हैं कि साहब, पैसा नहीं देते, यह नही करते,लेकिन वे भूल जाते हैं कि सरकार क्या करती हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाश भी तो मिलनी चाहिए। किसी ने यह शाबास नहीं दी। 19 करोउ़ टन अनाज पैदा हुआ। बाजार में रूलता रहा। अगर सरकार नहीं खरीदती तो 360 जो हमने मिनिम सपोर्ट प्राइस गेहूं की दी थी, उसको बाजार में ढाई सौ रूपये में कोई खरीदने वाला नहीं होता। यह सरकार की नीयत है और अर ऊंचा मिले तो बेचों। कॉटन का भाव हमने 1200 रूपये दिया। 2300 रूपये बेची हैं, 24 सौ रूपये बेची है और हमने उसको रोका नहीं कि ऐसा मत करो। तुम बेचो इसको भी हम करना चाहते हैं। इसर हिसाब से वह काम चले। ये सारी बातें इसमें निहित है, हमारी पालिसी मे हैं।

इसके साथ-साथ जो हमारी स्टेडिंग कमटी है उसने इसमें और लिखा हें। उन्होंने कहा है कि इसका विस्तार करो। विस्तार के बारे में कहा तो पोथा बन गया। नार्थ, साउथ, ईस्ट का इसमें फर्क नहीं रहेगा। मुझे सिर्फ छुट्टी दो कि मैं अलाहिदा-अलाहिदा जो जोन्स हैं उनमें अलाहिदा-अलाहिदा उसके कार्यकलाप का कर-कर के यहां क्या करना हैं, इसको इंप्लीमेंट यहां क्या करना हैं, इसमें बढ़ोत्तरी या घटोतरी क्या करना हैं, वह उसका करके हम चालू कर देंगे तो इसमें कहीं दिक्कत हैं? मैं यह बात नहीं मानने वाला हूं। यों तो आप छापा लगाओ, मोहर लगाओ, मेरा पथ-प्रदर्शन करो कि भाई बल राम आप इतना कर चुके इसमें थोड़ा सा और डाल दो। मैं आप के लिए हाजिर हूं। आपको मेरा पूरा योगदान मिलेगा। किसान मांग करता हैं, किसान का राइट हैं,तो उसको भी अधिकार हैं। हमें देना चाहिए। बाकी सब जगह मिल चुका हैं। उसको स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिएं। उसका क्या नहीं चाहिए। मैं जबब यहां के बच्चों को टमटम करते हुए देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूलों के बच्चे भी उसी बैचों पर बैठ करके कुछ पढ़ने की कोशिश

कर सकें और उनका मुकाबला कर सकें। मेरे वहां के बच्चे तो आई0ए0एस0 वगैरह मे आ ही नहीं, सकते, हम सोच ही नहीं सकते। यहां आपके पब्लिक स्कूल हैं, पैसे वालें स्कूल हे। हम तो उन स्कूलो में पढ़े हैं जहा बस्ते मे डोरी डाल स्कूल जाते थे। बैठने के लिए मां बोरी देती थी। वह भर लपेट करके आ जाया करते थे। वह कहती थी कि यह बैठने के लिए हैं और पता नहीं तुम जमीन पर कैसे लोट-पोट हो करके आ जाते हों। लेकिन आज तो यहां की जमीन पर पांव नहीं नहीं लगने देता। तो मैं थोड़ा सा उनके लिए भी चाहता हूं कि उनके चेहरे पर भी कुछ रौनक आए। उनके दिल में भी उमंग पैदा हो जो कि औरो के दिल में हैं। अब आपने टी0वी0 लगा दिए। घर-घर में टी0वी0 हैं। वह भी टी0वी0 के पास जाककर देख लेता है तो वह भी चर्चा करता है कि सिकन्दर बख्त जी की तरह चांदनी चौक से गुजरे। तो यह सारी बातें मैं करना चाहता हूं जिसके लिए आप की सहायता की जरूरत हैं।

श्री जगेश देसाई : मंत्री जी, यह जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, रेन फेड एरिया हैं, पल्स सीड हैं, ऑइल सीड हैं और कोर्स फूड ग्रेन के बारे में आने क्या किया?

श्री बलराम जाखड़ : उसमें भी उसी प्रकार से हम करना चाहते है और सिवाय के आज हमारे पास तकरीबन-तकरीबन भगवान ने, हमारे किसान ने और हमारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सहायता की हैं जहां कि हम 50 मिलियन से190 मिलियन पर पहुंच हुए हैं। हमने उसका हिसाब लगाया हैं और हमें एएक बूंद मंगवाने की भी कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ओ0जी0एल0 का ढिंढोरा इसलिए कर रखा हैं, मैं आप को बताना चाहता हूं कि जमाखोर होडिंग करके वक्त-बे-वक्त उसका पैसा बड़ा देते है। उसे रोकने के लिए यह किया हैं। जरूरत होती है तो उसको बंद कर देते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं हैं। दूध का उत्पादन बड़ गया हैं,ए मछली का उत्पादन 7 लाख से 48 लाख पर आ गया है कहीं नहीं रखी हैं, लेकिन जहां तक सीरियल्स की बात हैं, कोर्स काप की बात हैं, उसमे कमी नहीं हुई हैं। ज्वार हमारे पास हैं, लेकिन कोई खानेवाला नहीं है। आपने गेहूं दे-देकर, चावल दे-देकर आदत बिगाड़ दी हैं? ज्वार कोई नहीं खाता, बाजरा कोई नहीं खाता। पुराने जमाने में बाजारा खाया करते थे, लेकिन अब शान में फर्क पड़ता है बाजरा खाने से, हालांकि उस में ज्यादा इनग्रेडिएंट्स हैं, प्रोटीस ज्यादा हैं, लेकिन उसे हजम करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, लेकिन पल्सेस हमारे पास कम हैं और हमारे पास ही नही सारी दुनिया में कम हुए हैं।

श्री के0 आर0 मलकानी (दिल्ली) : पल्सेस क हैं तो एक्सपोर्ट क्यो हो रही हैं?

श्री बलराम जाखड़ : यह आप को गलतफहमी हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बाहर से मंगवाकर उस को रूपांर कर के वापिस कर सकता हैं, लेकि यहां से कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एकाध पहले कहीं किसी ने की, मुझे इतना ज्ञान हैं कि उस को अंडरटेकिंग थी कि एक किस्म की जो हमारे हिंदुस्तानी भाई खाते है, उस को भेज कर उसके बजाय डेढ़ा आएगा तग उस को दी जाएगी और कोई बाहर जाने का सवाल पैदा नहीं होता हैं। बाहर से मंगाने को सवाल जरूर हैं- आस्ट्रेलिया से, हंगारी से, थाईलैड से और टर्की से जहां कि ये पैदा होती हैं। अब माजरा यह हैं कि रेन-फेड़ क्रॉप विक्कलजीकल क्रॉप हैं। इसमे पैसा ज्यादा लगता हैं। सूखा भी ज्यादा पड़ता हैं तो आमदनी कम होती है और आप जानते हैं किसान वह चीज बोता है जोकि उसे फायदेमंद हो। कोई दुकानदार भी ऐसी खेती नहीं करेगा जोकि नुकसान वाली हो क्योंकि अगर नुकसान करेगी तो दुकान नहीं लेगी फिर हम भी किसान हैं और हम वह क्रॉप पैदा करेंगे जिस में फायदा होगा। आखिर हम किसी के बंधुआ मजदूर तो नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम मेहनत कर सकें और अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकें। इस के लिए हम ने इनसेंटिव दिया हैं और कीमत बढ़ायी हैं और ए क्रेसट के साथ मिलकर एक कमीशन बनाया है सिर्फ पल्सेस के लिए उन्होंने अरहर का बीज निकाला हैं,ड्वार्ड वेरायटी निकाली हैं, हायब्रिड निकाली हैं जोकि छोटा भी होगा और पकेगा भी जल्दी। अभी मैं परसों हैदराबाद से आया हूं। वहां "एक्रेसेप" से बात की थी, फिरोजा साहब को और उनके साथी हैं, उनको बताया कि मिलकर ऐसा काम करें कि जिस में नए बीज की उत्पत्ति हो, ड्राउट रेसिंस्टेट हो, फल देने वाला हो,ए पेस्अ रेसिस्टेंट हो क्योंकि इज़ में वावरल बहुत जल्दी लगता हैं। यह सारा अड़गा होता हैं, फायदा कम होता हैं, इसलिए किसान इस की खेती कम करता हैं। हम इसे ज्यादा उत्पादन वाला बनाना चाहते हैं ताकि इस का लाभ आप को मिल सके। हालांकि आज का 8 मिलियन से 14 मिलियन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह फिर भी कम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह और ज्यादा हो।

यह सारी बातें इसमें हैं। आप विस्तार से इसे देख लीजिएगा, और जो कुछ कमी लगे, मुझे बताइएगा। वह

मैं दूर करूंगा और आप को साथ लेकर किसान के माल को चमकाने का प्रयास करूंगा किसान यह कह सके कि मैं भी इस देश की प्रगति का भागीदार हूं। धन्यवाद।

श्री शंकर दया सिंह (बिहार) : उपसभाध्क्ष महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से, डिवोशन से और भावनात्मक रूप से भारत सरकार की कृषि नीति को यहां रखा हैं। इस में हम सभी का सहयोग आप को मिलेगा, इस में दो राय नहीं हैं, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो आप की कृषि नीति हैं, वह ऐसी न लगे किए वह संसद या भारत की कृषि नीति हैं, और इस बारे में मैं आप से विनती करना चाहता हूं कि देश के सभी भाषायी पत्रों में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम , बंगाला, जो भी गांव में जाता हो और उसमें आप किसानो से मांग करें कि इस तरह से भारत सरकार एएक नीति निर्धारित करने जा रही हैं, आप किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, गांवो मे रह रहे हैं, आप अपने सुझाव भेजिए। आप मानिए या न मानिए, लेकिन उनको इससे इतना अधिक संतोष हो जाएगा कि आप देखेंगे, लाखों लोग आपको पत्र भेजकर अपना इजहार करेंगे। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने इस बात को पहले ही कहा कि हर प्रांत से, हर जगह से फार्मर्स को बुला बुलाकर, बात करके यह कराया हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं अखबार में विज्ञापन की बात कर रहा हूं । ....(**व्यवधान**)....

श्री बलराम जाखड़ : विज्ञापन की बात नहीं, लेकिन मैने हर क्षेत्र से, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो किसान, वह विरोधी विचार का हो या समर्थक हो, सबको बुलाकर, बात करके यह किया हैं। जैसा मैंने आप से कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत पालिसी नहीं हैं, यह किसान की पालिसी हैं, यह आपकी पालिसी हैं, सब की पालिसी हैं।

उपसभाध्यक्ष (**कु0 सरोज खापर्डे**) : डा0 रणबीर सिंह ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडेन स्पीच।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम बैठी हैं और मैडेन स्पीच हो रही हैं।

डा0 रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैडम वाइस चेयर परयन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की पालिसी के ऊपर बोलने का मौका दिया। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी हल्की बैकग्राउंड देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती हैं और खेती के ऊपर निर्भर करती हैं। गांव की खुशहाली खेती की तरक्की से जुड़ी हैं और हिन्दुस्तान की तरक्की गांव की तरक्की से जुड़ी हुई हैं । मैं यह समझता हूं कि अगर खेती की तरक्की हो जाए तो हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती हैं। खेती जहां आबादी का पेट भरने के काम आती है वहीं इंडस्ट्री को रा-मैटेरियल सप्लाई करती हैं। एक्सपोर्ट के लिए मैटेरियल भेजती हैं, जिससे फारेन- एक्सचेंज देश के अन्दर आता हैं।

मैडम, खेती देश के रि पहलू के ऊपर असर डालती हैं। अगर खेती करने वालों की हालत सुधारी जाए तो उनकी जरूरतें बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ने से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और उससे एम्पलायमेंट मिलेगी। मैं इसकी डिटेल मे न जाकर अपनी बात की पुष्टि के लिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो अपनी वर्ष 1992-93 की बजट स्पीच मे कहा था, उसका एक सेन्टेन्स दोहरा देना चाहता हूं-

> "Agriculture is the foundation of our national prosperity and no strategy of economic development can succeed in our country if it does not ensure rapid growth of production and employment in agriculture nor can we hope to provide sufficient jobs for our growing rural labour force unless we can transform the economy of our rural areas."

इसी वक्त को वर्ष 1994-95 के इकोनोंमिक सर्वे में इस तरह से कहा गया हैं-

> "In overall economic development the agriculture sector will continue to lay a pivotal role since this sector still accounts for about 30 per cent of the GDP and almost two-thirds of the population still depends on this sector for livelihood."

मैडम, इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर खेती की अहहिमयत को समझा गया होता तो इसको सबसे ज्यादा प्रायरिटी देनी

5 चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती इस बात की रही कि आजादी के बाद खेती को उस प्रायरिटी का नहीं समझा गया और वह प्रायरिटी खेती को नहीं दी गई बल्कि देश में इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ ज्यादा सबकत दी गई और एग्रीकल्वरल को महत्व नहीं दिया गया। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका ख्याल यह बना कि वह इस देश को इंगलैंड के मानचेस्टर की तर हसे इण्डस्ट्रिलाइज कर दें। बस यही सबसे पहली भूल हो गई औश्र रूळ भूल उसके बाद बकायदा दोहराते चले गए आज तक। 48 बरस हो गए हम लोगों को आजाद हुए लेकिन एग्रीकल्वर को जो प्रियारिटी मिलनी चाहिए थी वह आज भी इसको नहीं मिली मुझे खुशी हैं कि हमारे माननीय एग्रीकल्वर मिनिस्टर साहब ने एक पालिसी बनाई हैं और उस पालिसी के तहत उन्होंने यह सोचा है कि देश के एग्रीकल्वर को इंडस्ट्री के बराबर लाएंगे, दूध में भी बढ़ोत्तरी करेंगे लेकिन मेरे अपने ,ख्यालात है जो मैं बताना चाहूंगा और जो थोड़ा सा बैकग्राएंड हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

जैसा कि पहले कहा कि जब हमें आजादी मिली तो शुरू में हमारे प्रधानमंत्री का ख्याल इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ गसा। हालांकि अपने कार्यकाल के आखिर हिस्से में भी इस गलती का अहसास हो गया था लेकिन यह गलती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसको सुधारा नहीं गया और जैसा मैंने कहा, यह गलती आज भी दोहराई जा रही हैं। इसके सबूत में मैं फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का एक जुमला, जो उन्होंने 1995-96 के बजट में बोला था, उसको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा थाः- The inadequacy of public investment in agriculture is today a matter of general concern इसके बाद वे फिर कहते हैं :-However, this is an area which is the responsibility of the States, who have neglected investment in infrastructure for agriculture."

तो आज तक हर हालत बनी हुई हैं कि आज भी एग्रीकल्वर के ऊपर खचें का जो हाल हैं वह ठीक तरीके से नही चलाया जा रहा हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में जो पूरा एलोकशन था, उसका 10 परसेंट एलोकेशन एग्रीकल्वर के लिए किया गया था जो बहुत कम था 75-80 फीसदी आबादी के लिए और एग्रीकल्वर जैसा मैंने बताया कि 30 परसेंट जी0डी0पी0 में जोड़ता हैं, उसके लिए 10 परसेंट इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। चौथी, पांचवी, पंचवर्षीय योजना मे इसको बढ़ाकर 12.9 परसेंट कर दिया गया, लेकिन यह भी बहुत कम था। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना मे इस एलोकेशन को घटा कर 5.7 कर दिया और घटाकर 5.2 परसेंट कर दिया गया। गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर इस अभाव का क्या असर पड़ा, उसमें कुछ आंकड़ें पेश करना चाहता हूं। 1957-58 में 18 करोड़ लोग थे जो पावटी लाइन से नीचे थे, 1973-74 में वे बढ़कर 22 करोड़ हो गए और 1993-94 में वे 35.48 करोड़ हो गए, जो करीब आबादी के 40 परसेंट लोग थे। एग्रीकल्वर लेबर के ऊपर इसका क्या असर पड़ा? 1960-61 में जो एक मजदूर की आमदनी थी वह 552 रूपए थी और कॉस्टेंट प्राइस के ऊपर 1975-76 में घटाकर वह 285 रूपए रह गई। रोड्स की हालत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में करीब 6 लाख गांव हैं, जिनमें से करीब सवा 3 लाख गांव ऐसे हैं, जिनमें सड़क नहीं हैं और 4 लाख से ज्यादा जा सकता हो मानसून में या ऐसी हालत में, वह एक्सेसिबल नहीं हैं। निट्रेसी की हालत यह है कि यू0पी0 में 36.6 परसेंट लिट्रेसी हैं और इंडिया में44.6 परसेंट लिट्रेसी हैं, यह गांव की हलत है और यह जो पालिसी हमारी रही हैं अब तक और जो नज़रिया रहा। गवर्नमेंट का यह उसका नतीजा हैं। इसके साथ-साथ हेल्थ की बात मैं बता दूं। आपकी एक डिस्पेंसरी 49 हजार लोगो के लिए गांव में हैं औ एक हास्पिटल का बैड 8,500 लोगों के लिए देहात के अंदर हैं। इसके अलावा थोड़ा पैसा खेती में इन्वेस्ट होने के बावजूद भी, जो भी पैसा खेती को मिला, मैं यह देखता हूं कि वह भी पूरा खर्च नहीं हुआ, थोड़ा पैसा मिला हैं, उसको भी खव्र नहीं किया गया। और उसमें से भी पैसा बाद में सरंडर किया गया।

5 P.M.

हमको दरअसल जैसा माननीय मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी पौलिसी के तहत काम करना पड़ेगा अगर हमको गांव की हालत सुधारनी हैं। यहां के किसानो की हालत की स्टडी करनी पड़ेगी और हमको उसी के मुत्ताबिक पौलिसी बनाकर टाईम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में 76.4 परसेंट छोटे और मार्जिनल किसान हैं। ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : डा0 सिंह, जरा एक मिनट आप बैठेंगे।

I would like to take the sense of the House. I would like to know whether the House is ready to sit beyond 5 O'clock.

श्री संघ प्रिय गौतम : हां, यह कल किया जाए। आज तो यह पूरा नहीं होगा।

कुछ सम्मानित सदस्य : हां, यह अच्छा हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : इसका मतलब हैं कि डा0 सिंह अपना अधूरा भाषण कल कंटीन्यू करेंगे।

In that case, I adjourn the House till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd August, 1995.